साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

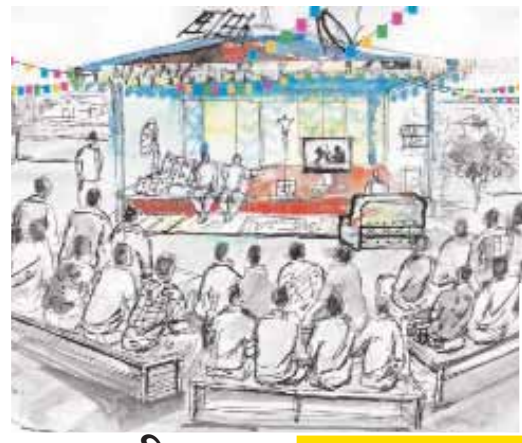

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 12 जुलाई 2021, वर्ष-7, अंक-15

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

- ओडीएफ पर सवालः खुले में शौच करने को मजबूर लोग
- खुली पोलः प्रदेश में लाखों शौचालय उपयोग लायक नहीं
- सरपंच और ग्राम सचिवों ने शौचालय में किया खूब खेल
- प्रदेशभर में सात वर्षों में 96,60,574 बनाए गए शौचालय
- निर्माण कागजों पर हुआ, 540 करोड़ के शौचालय ही गायब

खुले में शौच मुक्त मध्यप्रदेश में 'खेला'

अरविंद मिश्र, भोपाल

मध्यप्रदेश खुले में शौच मुक्त राज्य है। यानी 100 फीसदी ओडीएफ। मप्र को ओडीएफ बनाने के लिए सरकार ने 97,60,574 घरों में शौचालय बनवाए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये शौचालय कागजों में ही रह गए। प्रदेशभर में लाखों लोग आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। दरअसल, प्रदेशभर में जो शौचालय बनाए गए हैं या तो वे कागजों पर बने हैं या फिर गुणवत्ताहीन हैं। सरकार ने कई स्तरों पर इसकी जांच-पड़ताल भी की, लेकिन भ्रष्टाचारियों तक आंच नहीं पहुंची। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसके लिए घर-घर शौचालय के जरिए स्वच्छता की योजना परवान चढ़नी थी, मगर भ्रष्टाचार की गंदगी ने इसे भी गंदा कर डाला। भ्रष्टाचारियों ने गांव में शौचालय निर्माण की योजना को चूना लगा दिया। अब खुले में शौच मुक्त अभियान की सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। सरपंचों और ग्राम सचिवों ने शौचालय निर्माण में जमकर खेला किया।

सात साल में 96,60,574 शौचालय बनाए गए

मप्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सात साल में 96,60,574 शौचालय बनाए गए हैं। इनमें से स्वच्छाग्रहियों की मदद से 62 लाख 78 हजार 514 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। ये ऐसे घर थे, जिनमें रहने वाले सदस्य शौच के लिए खुले में जाते थे। वजह थी घर में शौचालय का नहीं होना। ऐसे 55 लाख 78 हजार 514 घरों में सरकार की मदद से शौचालय बनाए गए हैं। वहीं 7 लाख घरों में रहने वाले लोगों ने स्वेच्छा से शौचालय बनवाए हैं। लेकिन, हकीकत यह है कि आज लाखों शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, प्रदेशभर में लाखों शौचालयों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत मप्र में शौचालय निर्माण में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके पास कोई और कहीं की भी जानकारी हो तो शिकायत दर्ज कराइए। हम उसकी लोकायुक्त से जांच कराएंगे।

महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जिलावार बने शौचालय

जिला	शौचालय
सतना	364319
रीवा	360214
छिंदवाड़ा	354471
धार	348325
बालाघाट	287669
सागर	283331
खरगोन	267415
सिवनी	254650
बैतूल	235584
शिवपुरी	221943
मंडला	220853
दमोह	220702
देवास	217222
छतरपुर	217183
उज्जैन	214061
सीहोर	213894
रायसेन	211583
खंडवा	204767
मंदसौर	201722
कटनी	200589
बड़वानी	199008
विदिशा	198885
जबलपुर	189881
नरसिंहपुर	189602
टीकमगढ़	188770
झाबुआ	188436
रतलाम	185774
भिंड	181694
होशंगाबाद	181524
राजगढ़	180953
सीधी	180429
मुरैना	164571
डिंडोरी	158514
इंदौर	157949
शहडोल	156814
शाजापुर	156499
पन्ना	153930
सिंगरौली	150973
गुना	145337
अनूपपुर	142095
बुरहानपुर	126252
अलीराजपुर	111682
उमरिया	111073
श्योपुर	101125
ग्वालियर	110278
अशोकनगर	103389
नीमच	99036
हरदा	93580
भोपाल	88840
दतिया	83710
आगर मालवा	79474
कुल	9660574

बिना गड्ढे और सीट के बन गया शौचालय

प्रदेशभर में शौचालय निर्माण में जमकर घोटाले हुए हैं। न गड्ढा बनाया, न ही लगाई सीट, केवल दीवार खड़ी कर राशि आहरित कर ली गई है। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन, सतना, सीधी, बैतूल, सिंगरौली, खंडवा, बुरहानपुर सहित डेढ़ दर्जन जिलों की स्थिति का आंकलन करने के बाद पाया गया कि शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हो रहे हैं।

कोरोना काल में भी खुले में शौंच

कोरोना संक्रमणकाल में जब लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगा था, उस दौरान भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने खुले में थूकने के लिए प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की खुले में शौंच के लिए जाना मजबूरी बनी हुई है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान खुले में शौंच के लिए जाते समय कई बार पुलिस द्वारा गस्त के दौरान डंडे भी बरसाए गए। सीधी जिले की जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मड़वा ग्राम पंचायत के लोगों ने शौंचालय निर्माण के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया।

कागज पर बने 4.5 लाख शौचालय

बैतूल में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। तस्वीरों और पेपर पर तो 4.5 लाख शौचालय दिख रहे हैं। लेकिन स्पॉट पर जाने पर एक भी नहीं दिखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वह वहां से पलायन कर गए या फिर कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इसे बनाने में 540 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन सभी जीपीएस टैग फोटो भी थे, मगर मौके पर कहीं दिखा नहीं। जांच में यह बात सामने आई है कि जिन जगहों पर टॉयलेट निर्माण की बात कहीं जा रही है, वहां एक भी टॉयलेट नहीं मिले हैं। हालांकि प्रशासन के पास सभी टॉयलेट्स की जीपीएस-टैग की गई तस्वीरें हैं। पूरे खुलासे के बाद सरकार उन पर खर्च किए गए पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है।

इनका कहना है

वर्ष 2012 में प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया था और राज्य में बिना शौचालय के 62 लाख से अधिक गरीबी रेखा वाले घरों की पहचान की गई थी। दो अक्टूबर 2018 को, इन सभी शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया था। लेकिन पड़ताल में लगभग 4.5 लाख शौचालय गायब पाए गए। खुलासे के बाद सरकार उन पर खर्च किए गए पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है।

अजीत तिवारी, उप निदेशक,स्वच्छ भारत मिशन, मप्र

- मप्र में 15 अगस्त से लागू होगा मॉडल सिटीजन चार्टर
- बताना होगा कौन सा काम कितने समय में होगा पूरा

पंचायतों में सरपंच-सचिवों की तय होगी जवाबदेही

संवाददाता, भोपाल

गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। इसमें ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अब न केवल नागरिक सुविधाओं और समस्याओं के लिए ये जवाबदेह होंगे बल्कि तय समय सीमा में इन्हें काम करना होगा। मप्र में यह मॉडल सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। आम नागरिकों को नियम समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने वाली इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर से जिला स्तर तक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संचालक पंचायत राज बीएस जामोद को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर इसे लागू करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तन्वी सुद्रयाल सीईओ आरआरडीए और अपर संचालक पंचायत राज प्रद्युम्न शर्मा को दी गई है।

समस्याओं का समय पर होगा अब निराकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सबसे बड़ी समस्या थी गांव की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण न होना और इसके लिए जवाबदेही तय न होना। इसको देखते हुए केन्द्र के पंचायती राज मंत्रालय ने एक मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। जिसे मप्र में 15 अगस्त को लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के साथ ही ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिलना शुरू होगा और ऐसा न करने पर संबंधितों पर जवाबदेही भी तय होगी। केन्द्र द्वारा तय सेवाओं का परीक्षण कर राज्य स्तर पर इन सेवाओं का निर्धारण करने के प्रमुख सचिव ने संचालक पंचायत राज बीएस जामोद और भीमभाई पटेल संयुक्त संचालक पंचायत राज को जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इसके तहत काम की मांग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति, सड़क, नाली आदि सेवाएं शामिल की जा रही हैं।

ग्राम सभा होगी प्रभावी

मॉडल सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप मरम्मत, हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने की सुविधाएं भी ग्राम पंचायत उपलब्ध कराएगी। गांव का कोई भी निवासी अपनी ग्राम सभा से जन्म मृत्यु, विवाह सहित संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आसानी से तीन दिन में ले सकेगा।

सात दिन में नल कनेक्शन

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन योजनाओं के बाद भी लोगों के घरों में नल कनेक्शन नहीं लग पा रहा है और योजना सरपंच और सचिव के मनामानी और भ्रष्टाचार में घिर कर रह गई है। सिटीजन चार्टर के बाद आवेदन करने के सात दिन के अंदर कनेक्शन मिलेगा। पाइप लाइन में लीकेज या कोई खराबी होने पर 3 दिन में ठीक करना होगा। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट और बिजली कनेक्शन की भी समय सीमा तय की जाएगी।

30 दिन में अतिक्रमण हटाना होगा

सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण हटाने को लेकर सेवा में शामिल किया जाना है। इसकी समय सीमा 30 दिन करने पर विचार किया जा रहा है। गांव के खेल मैदान, पार्क, श्मसान, कब्रिस्तान, चरनोई की जमीन पर समय सीमा के अंदर अवैध कब्जे खाली करने होंगे। इसी तरह से पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमा भी तय की जा रही है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दिनांक से 30 दिन का समय सीमा तय की जा रही है।

» अपने घर पर ही डेढ़ सौ विलुप्तप्राय प्रजाति के पौधों को सहेजा

» ओमएजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में किया दर्ज

भोपाल की बेटी बनी मिनी जंगल की 'साक्षी'

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली एक पर्यावरण-प्रेमी युवती ने अपने घर को मिनी जंगल बनाया है। उन्होंने अपने आवास परिसर के साढ़े आठ सौ स्केवयर फीट में चार हजार से ज्यादा प्रजाति के पेड़-पौधों को लगाया है। ये युवती हैं प्रोफेसर साक्षी भारद्वाज, जिनकी इसी खूबी के चलते उनका नाम ओमएजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने राष्ट्रीय रिकार्ड के रूप में दर्ज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब इस पहल के बारे में पता चला तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए प्रोफेसर साक्षी भारद्वाज की तारीफ की और उनके इस प्रयास को अभिनंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से हरियाली बढ़ाने के लिए योगदान देने का आह्वान किया।

जंगलवास में चार हजार पौधे

साक्षी के घर जाएंगे तो देखकर चौंक जाएंगे कि यह घर है या जंगल। जब घर ही जंगल जैसे लग रहा है तो फिर इसका नाम भी साक्षी ने कुछ ऐसा ही रखा है जैसा आप सोच रहे होंगे। जी हां, उन्होंने अपने गार्डन को नाम दिया है-जंगलवास। इस जंगलवास में लगभग चार हजार पेड़-पौधे घर के बाहर और कुछ तो घर के अंदर भी लगे हुए हैं। साक्षी इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती हैं। वे कहती हैं कि पेड़-पौधों में भी जान होती है और ये स्पर्श को भली-भांति समझते हैं। इनकी साफ-सफाई, कांट-छांट में प्रेम और स्नेह के भाव का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई इन बातों का ध्यान नहीं रखता है, तो पेड़-पौधे उस तरह से नहीं बढ़ पाते, जैसे बढ़ना चाहिए या फिर वे सूख जाते हैं।

आठ हजार का एक पौधा

साक्षी के पास 150 प्रजाति के वे पेड़-पौधे हैं जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेजन से लेकर फ्लोरिडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपिंस आदि कई देशों से मंगाए इन पौधों को घर में बच्चों की तरह सहेजकर रखा है। इनमें से एक विशेष पौधा आठ हजार रुपए का है। वैरीगेटेड मोस्टेरा डेलीगोसिया अमेजन रेड फारेस्ट में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें सबसे ज्यादा आक्सीजन होती है।

तितलियों का इंतजार

यदि हम भारत की बात करें तो देशभर के विभिन्न प्रजाति के पेड़-पौधे साक्षी के पास हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों से लेकर एरनाकुलम, नागालैंड और अन्य प्रदेशों और शहरों से पौधों को मंगवाया है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर विभाग में सहायक व्याख्याता साक्षी भारद्वाज ने कहा कि मेट्रो शहरों में प्लांट कम्युनिटी होती है। यहां भी प्लांट कम्युनिटी बने। वह अब ऐसे पौधे लगाने की तैयारियां कर रही हैं, जिससे आकर्षित होकर तितलियां आ सकें।

मप्र में देश का पहला कोविड स्मृति वन

» भदभदा विश्राम घाटः लगाए जा रहे 56 प्रजाति के 4500 से ज्यादा पौधे

» सीएम शिवराज ने पत्नी साधना के साथ पौधा लगाकर किया आगाज

» रोपे गए पौधों में डाली जाएगी मृतकों की चिता की राख, गोबर की खाद

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला कोविड स्मृत वन तैयार किया जा रहा है। ये वन शहर के प्रमुख श्मशान घाट भदभदा पर बनाया जा रहा है। इसमें मृतकों की राख पौधों में डाली जाएगी। मृतकों के परिवार वाले उनकी याद में इस वन में पौधे लगा सकेंगे। 56 प्रजाति के 4500 पौधे रोपे जाएंगे। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है।

1200 वर्ग मीटर एरिया में रोपे जाने वाले पौधों की मिट्टी 21 डंपर भस्म, मिट्टी गोबर, खाद, लकड़ी बुरादा, रेत मिलाकर तैयार की गई है। इस तरह यह देश का पहला कोविड स्मृति वन होगा। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी, पूर्व मुख्य सचिव एसके मिश्रा, ममता मिश्रा, समता अग्रवाल, पूर्व विधायक रमेश शर्मा, प्रमोद चुग एवं कोरोना से मृत लोगों के परिजनों ने भी पौधे रोपे।

जापानी पद्धति का इस्तेमालः जापानी पद्धति मियावाकि से पौधे लगाने पर आसपास के वातावरण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्मी में भी पौधे हरे रहते हैं। इस तकनीक से पौधे लगाने पर पौधों की वृद्धि दोगुनी गति से होती है और आसपास के तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होती है।

इनका कहना है

कोविड काल में दिवंगतों की यादों को सहेजने के लिए इस स्मृति वन को विकसित कर रहे हैं। यहां पर मृतकों के परिजन आकर पौधे रोपे। पौधों के पेड़ बनने तक की सेवा प्रबंधन द्वारा की जाएगी। पौधारोपण की शुरुआज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है।

अरुण चौधरी, अध्यक्ष
भदभदा विश्राम घाट

कोविड काल के दौरान जिन दिवंगत आत्माओं का दाह संस्कार भदभदा विश्राम घाट में हुआ था और परिस्थितियों वश परिजन पूरी भस्म नहीं ले जा पाए थे। उस भस्म, मिट्टी, गोबर खाद, लकड़ी बुरादा, रेत, पेड़ों की पत्तियां, गौकाष्ठ का बुरादा मिलाकर जमीन को तैयार किया गया है।

अजय दुबे, कोषाध्यक्ष,
भदभदा समिति

जंगल के साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन

टेरिस गार्डन में फलदार पौधे लगाने पर फोकस

इधर, प्रदेश में जंगलों के साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय व निजी जमीनों पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने की तैयारी की जा रही है। यहां तक की टेरिस गार्डन व किचन तथा गमलों में भी छोटे-छोटे फलदार पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इसके लिए आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब बारिश शुरू हो गया है, इसलिए पौधारोपण में तेजी लाएं। निर्देश में कहा गया है कि शासकीय जमीनों के अलावा निजी जमीनों और खेत के मेढ़ पर भी पौधरोपण किया जाए। वहीं निजी जमीनों पर भी पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग द्वारा उद्यानिकी विभाग से सामंजस्य बनाकर फलदार पौधे आम, जामुन, कटहल, नींबू आंवला आदि की व्यवस्था की गई है, जो एक साल में छोटी सी जगह में तैयार हो जाएंगे।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त का अहम फैसला, बोले

अब पंचायत प्रतिनिधियों की भी 'कुंडली' होगी सार्वजनिक

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिए हैं। सिंह ने कहा है कि यह लोगों का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सूचना आयोग की ओर से यह फैसला एक शिकायत और अपील के प्रकरणों का निराकरण करते हुए सुनाया है। सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ पत्र आरटीआई दायर होने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की सभी जानकारी अब प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर एक क्लिक पर उपलब्ध कराई जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने को जनता का संवैधानिक अधिकार माना है। आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगने को भी आधार बनाया है।

नहीं होता नियमों का पालन

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर पंचायत चुनाव में निर्देश जारी किए जाते हैं कि उम्मीदवारों की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट और जिले के वेब पेज पर प्रदर्शित की जाए। हालांकि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। वहीं, ओडिशा में पंचायत उम्मीदवारों की सारी जानकारियां वहां के जिले के वेब पेज पर उपलब्ध है। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में यह जानकारियां वेब पेज पर उपलब्ध हैं। कर्नाटक में भी नगरीय निकाय से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी, शपथ पत्र आदि उपलब्ध है।

जनता को जानकारी का अधिकार

आयोग का मानना है कि जैसी कसावट और पारदर्शिता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होती है, वैसी ही पंचायत चुनाव में भी होनी चाहिए। मतदाताओं को यह जानने का हक है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने चुनाव दर चुनाव कितनी संपत्ति अर्जित की है या उनके खिलाफ कौन से अपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग से इस आदेश का पालन सभी कलेक्टरों से कराने को कहा गया है।

यह है मामला

आरटीआइ एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई के तहत रीवा जिले में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि के शपथ पत्र की जानकारी मांगी तो तहसीलदार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जानकारी राज्य चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार सील बंद लिफाफे में है और उसे खोलने का उन्हें अधिकार नहीं है।

इसके बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा तो पता चला कि शपथ पत्रों को सीलबंद लिफाफे में रखने का नियम नहीं है, बल्कि मतपत्र को सीलबंद लिफाफे में रखने का नियम है। इस अपील के अलावा शिवानंद द्विवेदी ने एक शिकायत भी राज्य सूचना आयोग के समक्ष रखी, जिसमें रीवा संभाग के अलावा अन्य जिलों में वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को सामने रखा।

प्रदेश में वन विभाग शुरू करेगा यूट्यूब चैनल

» राष्ट्रीय उद्यान्न-अभयारण्यों और चिड़ियाघरों को ऑनलाइन जोड़ेंगे

» घर बैठे देख सकेंगे अभयारण्यों में विचरते जंगली जानवरों को

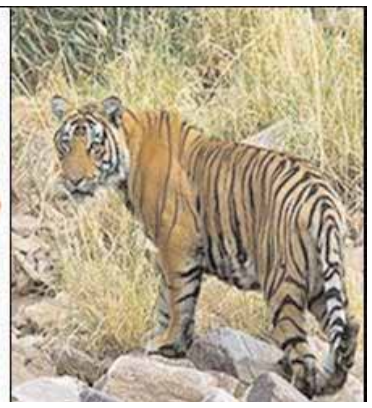

संवाददाता, भोपाल

वैसे तो नेशनल जॉग्रोफी, डिस्कवरी जैसे चैनलों पर वाइल्ड लाइफ देखने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रसारित होते हैं, लेकिन अब मध्यप्रदेश का वन विभाग अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन लाइव राष्ट्रीय उद्यान्नों, अभ्यारण्यों का प्रसारण होगा और शहर सहित अन्य जंगली जानवर इस लाइव प्रसारण के जरिए घर बैठे देखे जा सकेंगे। प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। जंगलों में वैसे भी कई जगह कैमरे लगाए जाते हैं, ताकि जानवरों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा सके। खासकर शेर, बाघ, तेंदुआ और इस तरह के अन्य जानवरों पर। प्रदेशभर में कई राष्ट्रीय उद्यान्न, अभ्यारण्य से लेकर चिड़ियाघरों में ये जानवर मौजूद हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग इन अभ्यारण्यों की सैर करने जाते हैं, ताकि लाइव शेर सहित अन्य जंगली जानवरों को निहार सकें। उसी तरह अब घर बैठे इन जानवरों को रियल टाइम यानी देखा जा सकेगा। जब भी ये यूट्यूब खोला जाएगा, तब उसी वक्त का सीधा यानी लाइव प्रसारण अभ्यारण्यों का नजर आएगा। वन विभाग इसके लिए सभी अभ्यारण्यों में ट्रैप कैमरे सहित अन्य सुविधाएं जुटा रहा है। इससे जानवरों के घायलों से लेकर अन्य जानकारियां भी रियल टाइम में ही विभाग को मिल जाएगी।

इनका कहना है

जब भी ये यूट्यूब खोला जाएगा, तब उसी वक्त का सीधा यानी लाइव प्रसारण अभ्यारण्यों का नजर आएगा।

साथ ही एक बाल सखा अभिनव योजना भी शुरू की जा रही है, जिसके जरिए बाघ एवं अन्य वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में जागरूकता लाई जा सकेगी। टाइगर फाउंडेशन सोसायटी द्वारा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करवाने के लिए 4 हजार से अधिक टी-शर्ट भी तैयार करवाई गई है। ये टी-शर्ट टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के समीप रहने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाएगी।

विजय शाह, वन मंत्री

निर्मल भारत के तहत गांव होंगे कचरा मुक्त

» घर-घर से कलेक्ट किया जाएगा कचरा » साफ सफाई पर होगा शासन का फोकस » भांडेर ब्लॉक की 21 पंचायतों का चयन

संवाददाता, भोपाल

निर्मल भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कूड़ा एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य गांवों को कचरा मुक्त बनाना है। गांव में घर-घर से कचरा कलेक्ट किया जाएगा। ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ताकि गांव में भी शहर की तर्ज पर कचरा प्रबंधन हो सके। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से प्रथम चरण में भांडेर ब्लॉक के 21 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। दरअसल, शहरों को साफ और सुंदर बनाने के साथ ही अब गांव कूड़ा-कचरा से मुक्त होंगे। गांवों में ठोस कूड़ा-कचरा व तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए गांव में उचित प्रबंध किए जा रहे हैं।

पंचायतें होंगी स्वच्छ

निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य ही ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबंधन के माध्यम से ही व्यवस्था के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, गांव में बेकार पड़ा ठोस कूड़ा-कचरा पंचायतों के लिए आमदनी का एक साधन भी बन सकता है। इससे ग्राम पंचायतें स्वच्छ व समृद्ध बनेगी।

संख्या के आधार पर निर्धारण

इस परियोजना के तहत गांव में कम्पोस्ट-पिट, वर्मी-कम्पोस्टिग, गड्ढा, सोखता गड्ढा, गंदे पानी का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरे को घर-घर से इकट्ठा करना, एक स्थान पर ले जाना, गलनशील व अगलनशील कचरे को अलग-अलग करना तथा उसका सही रूप से निपटान करने के लिए काम कराए जाएंगे। ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए हर पंचायत में 4 लाख 97 हजार का बजट तय किया गया है।

खरीदे जाएंगे ई रिक्शा

प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद घरों से कचरा कलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए जिन ग्राम पंचायत में कचरा प्रबंधन का प्रोजेक्ट तैयार होगा, उसके द्वारा ई रिक्शा क्रय किए जाएंगे। जिनके माध्यम से गांव गांव जाकर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। जिसे लाकर एक जगह एकत्रित किया जाएगा। जिसके बाद इस कचरे का प्रबंधन किया जाएगा।

नदियों का प्रदूषण: धार्मिक भाव से नहीं साफ होंगी, इनकी जरूरत को समझना होगा

शंभूनाथ शुक्ल

नदियों में बढ़ता प्रदूषण पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। पिछले दिनों बनारस में गंगा का पानी हरा हो गया था। किसी भी नदी का पानी हरा होने का मतलब प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और पानी के ऊपर काई जम रही है। किसी भी नदी का पानी अपनी धारा में अवरुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि नदी की धारा अगर अवरुद्ध हो गई तो चाहे गर्मी हो या सर्दी अथवा बरसात वह कहर ढा देगी, पर यह जरूर हुआ होगा, कि बनारस में घाटों की तरफ आने वाली धारा ने अपना रूट बदल लिया होगा। ऐसा हुआ तो भी यह चिंता का विषय है।

नदियों में बढ़ता प्रदूषण पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। पिछले दिनों बनारस में गंगा का पानी हरा हो गया था। किसी भी नदी का पानी हरा होने का मतलब प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और पानी के ऊपर काई जम रही है। किसी भी नदी का पानी अपनी धारा में अवरुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि नदी की धारा अगर अवरुद्ध हो गई तो चाहे गर्मी हो या सर्दी अथवा बरसात वह कहर ढा देगी, पर यह जरूर हुआ होगा, कि बनारस में घाटों की तरफ आने वाली धारा ने अपना रूट बदल लिया होगा। ऐसा हुआ तो भी यह चिंता का विषय है। क्योंकि कहा जाता है कि बनारस जब से बसा, कभी गंगा ने अपनी धारा नहीं बदली। यही गंगा की और बनारस की खासियत है। गंगा के पानी में जो गुण है, उसके चलते गंगा के बहते पानी में काई नहीं जम सकती। अबुल फजल ने आइने अकबरी में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर के पीने के लिए गंगा जल ही लाया जाता था और बाकी इस्तेमाल के लिए जमना का पानी। जब बादशाह आगरा में होते तो गंगा जल सोरों (वर्तमान में मान्यवर कांशीराम जिले के अंतर्गत गंगा तट पर बसा कस्बा) और जब दिल्ली या लाहौर में होते तो हरिद्वार से गंगाजल लाया जाता। बाकी उनका भोजन बनाने के लिए यमुना का जल प्रयोग में लाया जाता था जो दिल्ली और आगरा में सहज सुलभ था। मुगल बादशाहों के लिए गंगा जल लाए जाने की यह परंपरा जहांगीर तक चली और बाकी के बादशाह अपने पूर्ववर्तियों के लिए यमुना का जल ही प्रयोग करते रहे। यही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में वहां के राजा या नवाब अथवा सुल्तान अपने पीने के लिए स्थानीय नदियों के जल पर अधिक भरोसा करते थे। तब कुआं, बावड़ी, झीलों व तालाब का पानी बाकी काम के लिए ही प्रयोग होता था। यही नहीं, जॉब चार्नाक सन 1699 में बंगाल के तट पर उतरा और उसने कोलकाता नगर बसाया तो पीने के पानी के लिए हुगली नदी का जल इस्तेमाल करता था। इस जल को उबाल कर पिया जाता था। अभी कुछ वर्षों पहले तक कोलकाता में हुगली पर जब भी रात को ज्वार आया करता तो सड़क किनारे के नल अपने आप बहने लगते और सड़कें स्वत: ही साफ हो जाया करतीं। अब सभ्यता के विकास के साथ ही नदियों का जल कहीं भी पीने लायक नहीं बचा है। हर नदी प्रदूषित है। गंगा का हाल तो यह है कि हरिद्वार तक आते-आते गंगा का जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि उस जल से आचमन तक करने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर गंगा की ही बात करें तो पाएंगे कि गंगा में बांध बनने और औद्योगिक कचरा लगातार इस नदी में गिराए जाने के कारण यह नदी आज दुनिया की सातवीं सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाने लगी है। 1854 में गंगा में पहला बांध हरिद्वार में बना और एक अपर गंगा कैनाल नाम से एक नहर निकाली गई। इसके बाद बना फरक्का और गंगा की धारा अवरोधित होती गई। जाहिर है कि अगर नदी की मुख्य धारा को अवरोधित किया गया तो जलीय जीव-जंतु तो प्रभावित होते ही हैं साथ में गाद के जमने की तीव्रता भी बढ़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि गंगा को स्वत: साफ करने वाली धारा बाधित होती गई और फिर शहरों के किनारे का कचरा और गंदगी तथा औद्योगिक वेस्टेज ने इसकी हालत एक नाले की तरह बना दी। आज गंगा में गंदगी गोमुख से ही शुरू हो जाती है और गंगोत्री तक आते-आते गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी होती है कि इसका पानी पीने लायक नहीं रहता। गंगोत्री से महज 40 किमी की दूरी पर ही एनटीपीसी के बांध ने इसका रास्ता बाधित कर दिया है। आज गंगोत्री से चंबा के बीच गंगा में इतने अधिक बांध और बैराज हैं कि नदी की धारा कहीं भी अपने मूल स्वरूप में बह नहीं पाती और यही कारण है कि 2013 में ऐसी तबाही मची कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक पूरा पर्वतीय इलाका अस्त-व्यस्त हो गया। अभी तक सरकार की परियोजनाओं के तहत अकेले उत्तराखंड में ही 300 बांध बनने प्रस्तावित हैं। हमारी नदियों की देखरेख का अभाव और उनके जल के लगातार दोहन का यह नतीजा यह है कि निकट भविष्य में पीने के लिए भी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। शायद लोग इस हकीकत से रूबरू नहीं हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो भी जल स्रोत हैं उनमें से 97 प्रतिशत तो खारे पानी के हैं और सिर्फ तीन प्रतिशत जो हैं वे जमे हुए हैं और इन्हीं जमे हुए स्रोत से ही नदियां निकलती हैं जो हमारे लिए पेयजल उपलब्ध कराती हैं। अब अगर ये नदियां भी प्रदूषित होती गईं तो पीने के लिए भी पानी कहां से लाया जाएगा। यमुना के दाएं किनारे और बाएं किनारे दोनों तरफ आठ-आठ किमी तक खारा पानी हो गया है। यहां कुएं, बावड़ी और जमीन के अंदर के जल स्रोत भी खारे हैं, इसीलिए यमुना किनारे बसने वालों के लिए पानी गंगा के पानी ट्रीट कर लाया जाता है। दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद इसके उदाहरण हैं। आज भी गंगा और नर्मदा ही दो ऐसी नदियां मानी जाती हैं जिनका पानी सबसे अधिक पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भले इस पानी को ट्रीट करना पड़ता हो, क्योंकि इन दोनों ही नदियों का पानी कहीं भी खारा नहीं है। लेकिन क्या यह दुर्भाग्यशाली नहीं है कि गंगा लगभग 2500 किमी के कुल बहाव क्षेत्र की शुरुआत में ही इतनी अधिक प्रदूषित हो जाती है कि समुद्र तक जाते-जाते वह एक गंदा नाला बनकर पहुंचती है। गंगा उत्तराखंड में करीब 450 किमी बहती है और इस क्षेत्र में ही 14 नाले इसमें 450 मिलियन घन लीटर गंदा पानी इसमें उड़ेलते हैं। इसके बाद यूपी के 1000 किमी का बहाव इसे और प्रदूषित करता है। फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर इस नदी में करीब 3 हजार मिलियन घन लीटर प्रदूषित पानी फेकते हैं। जबकि यह वह नदी है जिसके सहारे देश की 50 करोड़ आबादी पलती है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी।

खत्म होगी पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या! समुद्र का प्लास्टिक बन जाएगा पानी

पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समुद्री प्रदूषण भी है। ये एक ऐसी समस्या है, जिसपर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। एक हालिया रिसर्च के अनुसार, संभव है कि साल 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक ही मौजूद हो, लेकिन कई स्तर पर इस समस्या से निपटने की लगातार कोशिशें भी हो रही हैं। समुद्री जीवन को सुरक्षित रखने और पृथ्वी को संभावी संकट से बचाने के लिए लगातार रिसर्च भी किए जा रहे हैं। इसमें से कुछ रिसर्च तो आपको चौंका भी सकते हैं। अब इसी क्रम में एक तरह के खास बैक्टिरिया की खोज की गई है। इसे दो स्टूडेंट्स जेनी याओ और मिरांडा वैंग ने तैयार किया है. ये दोनों स्टूडेंट्स अपने स्कूल के दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। अंतत: अब उनके इस कड़ी मेहनत का फल हकीकत में बदलने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इन दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी इस खास खोज का पेटेंट भी करा लिया है और प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उन्हें 4 लाख डॉलर का फंड भी मिल चुका है। इन दोनों स्टूडेंट्स की उम्र महज 20 साल है। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें अब तक 5 प्राइजेज भी जीतने का मौका मिला है। इतनी कम उम्र में पर्लमैन साइंस प्राइज जीतने के बाद उनकी पॉपुलेरिटी भी बढ़ी है। दरअसल, इन दोनों स्टूडेंट्स ने एक खास तरह का बैक्टिरिया को तैयार किया है जो प्लास्टिक और कार्बन डाईऑक्साइड और पानी में तब्दील कर देता है। इस टेक्नोलॉजी को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे समुद्री किनारे यानी बीच साफ करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ में कपड़ों के लिए कच्चे माल का इंतजाम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर मिरांडा वैंग का कहना है, स्वाभाविक रूप से लोगों द्वारा पूरी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कराना लगभग असंभव है। ऐसे में हमें एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो प्लास्टिक को नष्ट कर दें। इस प्रकार संभवत: हर चीज बायोडिग्रेडेबल बन सकेगा। इस टेक्नोलॉजी के लिए दो पड़ाव बेहद खास हैं। पहला तो यह कि प्लास्टिक को घोला जाए और एंजाइम की मदद से प्लास्टिक को उच्च कोटड़ि के लचीजे पदार्थ में कंवर्ट किया जाए। फिर इन कम्पोनेंट को बायोडाइजेस्टर स्टेशन पर रखा जाएगा। यहां पर इन्हें बैक्टिरिया के लिए खाना परोसने के तौर पर रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 24 घंटे जारी रखना होगा। इतने समय में प्लास्टिक को पानी में कंवर्ट किया जा सकेगा। प्लास्टिक एक जटिल पॉलीमर होता है। आसान भाषा में समझें तो प्लास्टिक मॉलीक्युल्स को लंबा और बार-बार दोहराया गया चेन है जो पानी में कभी घुलता नहीं है। इन चेन्स की मजबूती की वजह से ही प्लास्टिक लंबे समत टिकता है। प्राकृतिक रूप से इस नष्ट होने में लंबा समय लगता है। अगर इन्हें छोटे और घुलनशील ईकाई तब्दील कर दिया जाए तो इन्हें नये प्लास्टिक के तौर पर बनाया जा सकता है।

बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन में क्यों हो रही देरी

पंकज कुमार

जायडस कैडिला कंपनी ने जायकोव वी-डी वैक्सीन के लिए आपात कालीन मंजूरी के लिए आवेदन दिया है। यह देश के लिए राहत की बात है और इसकी वजह ये है कि यह पहला वैक्सीन है जिसने अपने क्लिनिकल फेज ट्रायल में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल किया है। सवाल अभी भी यही है कि बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे वैक्सीन में हो रहे विलंब की आखिरकार वजह क्या है और कब तक भारत में बच्चों के लिए समुचित मात्रा में वैक्सीन तैयार हो सकेगी। जायडस कैडिला द्वारा तैयार की गई वैक्सीन के ट्रायल में किशोरों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्लाज्मिड डीएनए आधारित वैक्सीन की खासियत यह है कि एंटीजन विशिष्ट एंटीबॉडी तैयार करने की इस वैक्सीन में क्षमता है जो बी और टी सेल दोनों को शरीर में तैयार करता है। जाहिर है बी और टी सेल से समुचित मात्रा में एंटीबॉडी तैयार होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वैक्सीन के तीनों फेज का ट्रायल सबसे ज्यादा 28 हजार वॉलंटियर्स को शामिल करते हुए किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये साल में 12 करोड़ डोजेज तैयार करेगा जो 40 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। रॉयटर के मुताबिक वैक्सीन सुरक्षा और प्रभावकारिता दोनों के मापदंड पर खरा उतरा है। इसलिए दूसरी लहर के बाद युवाओं और बच्चों में होने वाले कोविड बीमारी की गंभीर खतरों से निपटने में जायकोवी-डी कारगर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेगुलेट्री बॉडी द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट कर उन्हें संभावित तीसरी लहर के खतरों सो बचाया जा सकता है। दूसरी लहर में अधिक तादाद में बच्चे कोविड बीमारी से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद उनके सुरक्षा को लेकर देश में चिंता जताई जाने लगी है। नामचीन पीडियाट्रिशियन डॉ. रवि सरीखे चिकित्सकों ने तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की तरफ देश का ध्यान खींचा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बच्चों के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन की जरूरत को लेकर कई बार अपनी राय सामने रखी है। यही वजह है कि बच्चों के लिए भारत बायोटैक ने वैक्सीन तैयार करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया है। एम्स के चिकित्सक डॉ. संजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीन महीनों के बाद बच्चों के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल, कोवैक्सीन का ट्रायल दो साल और उसके ऊपर के बच्चों पर किया जा रहा है और उसके नतीजे अभी तक सकारात्मक बताए जा रहे हैं, लेकिन कोविड की तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह के बीच आने की खबरों की वजह से बच्चों के वैक्सीन को लेकर लोगों की चिंता चरम पर है। इसकी वजह खास तौर पर इसलिए भी है, क्योंकि दूसरी लहर के दरमियान पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में एमआईएस (सी) की गंभीर बीमारी सामने आ रही है। बच्चों का वैक्सीनेशन उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं है बल्कि हर्ड इम्युनिटी के लिए भी ये बेहद जरूरी है। पहली लहर में बच्चों का संक्रमित होना बहुत कम देखा गया था, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी अच्छी संख्या में संक्रमित हुए हैं और इसकी वजह वायरस का इम्युनिटी को इवेड करना यानि कि चकमा देना है। इसलिए वैक्सीन नहीं लगने की वजह से बच्चों पर खतरा ज्यादा है। दुनियां के कुछ देशों में जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, जापान, इजरायल और यूरोप के कुछ हिस्सों में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने की अनुमति दी जा चुकी है। इन देशों में दी जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल साल 2020 के अंत में शुरू हो पाया था। फाईजर बायोटेक, मॉर्डना और साइनोफॉर्म जैसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल साल 2020 के अंत में ही शुरू हो पाया था। इन देशों में एमरजेंसी यूज का परमिशन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिया जा चुका है। चीन ने एक कदम आगे बढ़कर होम मेड वैक्सीन साइनोफॉर्म को 3 साल के बच्चों के इस्तेमाल के लिए परमिट कर दिया है। भारत में भारत बायोटैक का क्लिनिकल ट्रायल जारी है जो दो साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में मार्डर्ना को परमिशन दे दिया है। वहीं फाइजर और बायोटैक से बात चल रही है जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि साल 2021 के अंत तक ही देश में बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी।

जंगल में पाए जाने वाले सलई के पेड़ आदिवासियों के ला रहे अच्छे दिन

सलई का गोंद बदलेगा किस्मत

संवाददाता, श्योपुर

मध्यप्रदेश के जंगल में पाए जाने वाले सलई के पेड़ आदिवासियों की किस्मत बदल रहे हैं। अभी तक आदिवासी इसका उपयोग अपनी सामान्य आजीविका के लिए करते रहे हैं। पेड़ से निकलने वाली सुगंधित गोंद का उपयोग दवा, परफ्यूम आदि में किया जाता है। इसे देखते हुए गोंद का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात की फार्माजा हर्बल कंपनी इन आदिवासियों के साथ आई है। प्रदेश में श्योपुर जिला सलई का गोंद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

फार्माजा हर्बल कंपनी ने वन समितियों के माध्यम से ओछापुरा क्षेत्र में 25 हेक्टेयर में सलई के पौधों का रोपण शुरू किया है। यह पौधे भी आदिवासी जंगल से लाकर रोप रहे हैं। कंपनी तीन साल तक हर साल 10 लाख रुपए पौधे लगाने से लेकर उनकी सुरक्षा पर खर्च करेगी। पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपए दिए भी जा चुके हैं। पेड़ बड़े होने के बाद इन्हें आदिवासियों को ही सौंप दिया जाएगा। इसके बाद आदिवासी इससे निकलने वाली गोंद को बेच भी सकेंगे।

आदिवासी ही निकालेंगे गोंद

गुजरात की कंपनी ने सलई के पेड़ लगाने का काम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों (सीएसआर प्रोग्राम) के तहत शुरू किया है। कंपनी ने ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया है कि पेड़ों से निकलने वाली गोंद को वह ले जाएगी, बल्कि पेड़ तैयार होने के बाद वन समितियों के माध्यम से जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवारों को ही सुपुर्द किए जाएंगे। आदिवासी परिवार ही पेड़ों से निकलने वाली गोंद निकालेंगे और बाजार में या कंपनी को बेच सकेंगे। इससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

आदिवासी दहेज में भी देते हैं पेड़ों को

छह से आठ माह में सलई का पेड़ आकार लेने लगता है। गोंद निकालने के लिए पेड़ के तने को चारों ओर जमीन से दो से तीन फीट ऊपर कुल्हाड़ी से छील देते हैं। आठ से 10 दिन के बाद इससे गोंद निकलना शुरू हो जाती है। जंगल में खड़े सलई के पेड़ों को आदिवासी अपना अधिकार मानते हैं। चूंकि इन पेड़ों से गोंद निकलने से उन्हें रोजगार मिलता है, इसलिए वे इन्हें तस्करों से भी बचाते हैं। यही नहीं, बेटी की शादी में वर पक्ष को उपहार के रूप में भी पेड़ देते हैं, जिससे उनकी बेटी आर्थिक रूप से परेशान न रहे।

गिरवी रखते हैं पेड़

जंगल में आदिवासी ही सलई के पेड़ से गोंद निकालकर उपयोग करते हैं। पारंपरिक रूप से इन पेड़ों पर इन्हीं का एकाधिकार माना जाता है। किसी पेड़ पर मालिकाना हक आदिवासियों का मुखिया सबकी सहमति से तय करता है। एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक माह में आसानी से 50 किलो तक गोंद निकल आता है। बाजार में एक किलो गेंद की कीमत करीब 400 रुपए है। ऐसे में जिस आदिवासी के पास कोई पेड़ रहता है, वह जरूरत पड़ने पर गिरवी भी रख देता है जिससे उसे 15 से 20 हजार कर्ज के रूप में आसानी से मिल जाते हैं। जब तक कर्ज नहीं पट जाता है, गोंद को निकालकर बेचने का काम कर्जदाता ही करता है।

जंगल सुरक्षित

जंगल के पेड़ को इस प्रकार दहेज में देने और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेने की व्यवस्था को लेकर वन विभाग अधिकारियों को कहना है कि यह आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था है चूंकि पेड़ काटे नहीं जाते और न ही जंगल को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं रहती।

इनका कहना है

हमारी कंपनी ने श्योपुर को इसलिए चुना है, क्योंकि यहां बोसवेलिया सेराटा (सलई से निकलने वाली गोंद का वैज्ञानिक नाम) के पेड़ों का प्राकृतिक जंगल है। हमारी कंपनी भी इसी क्षेत्र से बोसवेलिया खरीदती है। कंपनी श्योपुर में 25 हेक्टेयर में सलई के पौधे लगवा रही है। यह काम कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत करवा रही है। आदिवासी यदि कंपनी को अपना उत्पाद बेचते हैं तो कंपनी इसके लिए भी उनकी मदद करेगी।

डॉ. श्वेता सिंह, वैज्ञानिक, फार्माजा हर्बल कंपनी, गुजरात

गुजरात की कंपनी ओछापुरा में 25 हेक्टेयर में सलई के पौधों का प्लांटेशन वन समितियों के माध्यम से कर रही है। सलई की गोंद सुगंधित होती है। इसका उपयोग दवा के साथ-साथ परफ्यूम आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे में औषधियों का व्यापार करने वाली कंपनी का आदिवासियों से जुड़ने से आदिवासियों को फायदा होगा।

सुधांशु यादव, डीएफओ, सामान्य वन मंडल, श्योपुर

बारिश नहीं होने से कई तरह के कीट या दीमक का खतरा

» कृषि वैज्ञानियों से सलाह लेकर खेतों में कर रहे छिड़काव

» अब बारिश की लंबी खेंच ने किसानों की बढ़ा दी चिंता

संवाददाता, हरदा

मानसून की बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। फसल भी प्रभावित होना शुरू हो गई है। बारिश नहीं होने से कई तरह के कीट या दीमक का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में किसान कृषि विज्ञानियों से सलाह लेकर खेतों में छिड़काव करा रहे हैं। बारिश की लंबी खेंच ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेत में नमी बनी रहे, इसके लिए किसानों ने कुलपा भी कर दिए हैं। लेकिन तेज धूप से तापमान बढ़ने कुलपा होने के बाद भी खेतों से नमी गायब हो गई। किसानों की फसल मुरझाना शुरू हो गई है। किसानों ने बताया कि एक-दो दिन में बारिश नहीं होने पर सोयाबीन, उड़द की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच रही है। जिले में जिले में 97 फीसद बोवनी हो चुकी है।

फसल को बारिश की जरूरत: हंडिया तहसील के ग्राम कचबैड़ी के किसान कपिल जाट ने बताया कि फसल को बारिश की जरूरत है। बारिश की लंबी खेंच के कारण फसलें प्रभावित हो रही है। पानी की कमी से सोयाबीन, उड़द की फसल पर ज्यादा असर पड़ रहा है। सिराली तहसील के ग्राम धूपकरण के अनिल झंवर ने बताया दो-तीन में बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगा।

दोबारा बोवनी से अतिरिक्त बोझ: जिले के कई गांव में बारिश के लंबी खेंच और अमानक बीज के अंकुरित नहीं होने से बोवनी खराब हो चुकी है। महंगे दाम पर खरीदे गए सोयाबीन के बीज का अंकुरण नहीं होने के कारण किसानों को दोबारा बीज खरीदकर बोवनी करना पड़ा। वहीं जो किसान महंगा बीज नहीं खरीद सके। उन्होंने दूसरी फसल मक्का, मूंग, उड़द की बोवनी करने की तैयारी की है। इसके कारण किसानों अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। इससे बोवनी की लागत भी बढ़ गई है।

पिछले साल से कम हुई बारिश: जिले में पिछले साल की तुलना में अब तक 133.4 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। इस वर्ष के मानसून सत्र में बारिश कम होने से उमस बनी हुई है। जिले में चालू मानसून मौसम के दौरान एक जून से अब तक 184.5 मिलीमीटर हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधी की औसत वर्षा 317.9 मिलीमीटर हुई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख के अनुसार अभी तक हरदा में 232.6 (गत वर्ष 390.3) मिलीमीटर, टिमरनी में 244.9 (गत वर्ष 284.8) मिलीमीटर, खिरकिया में 76.0 (गत वर्ष 278.6) मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिले की सामान्य वर्षा 1261.7 मिलीमीटर है।

इनका कहना है

जिले में अब तक 97 फीसद खरीफ सीजन की बोवनी हो चुकी है। इस वर्ष जिले में सात हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की बोवनी की गई है। जबकि सोयाबीन की फसल एक लाख 13 हजार हेक्टेयर में बोई गई। फसल को पानी की जरूरत है।

-कपिल बेड़ा, सहायक संचालक, कृषि, हरदा

मुरैना में उपयंत्री, एई और पंचायत सचिवों पर सीईओ की गाज

जिला पंचायत सीईओ ने गुणवत्ता खराब होने की कार्रवाई

मुरैना। जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह कैलारस, पहाड़गढ़ सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। विकास कामों की गुणवत्ता ठीक न होने पर एक सब इंजीनियर और सहायक यंत्री का एक सप्ताह का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। उन्हें नोटिस भी दिया गया। इसके बाद समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में पांच पंचायत सचिव नहीं पहुंचे। जिस पर उन्होंने उनका एक-एक सप्ताह का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीईओ रोशन कुमार सिंह ने पहाड़गढ़ जनपद की ग्राम पंचायत अगरौता, सिकरौदा, चचेड़ी व झोड़ पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत अगरौता की गौशाला के अलावा, सिकरौदा तथा ग्राम पंचायत चचेड़ी में चल रहे काम अधूरे पाए गए। कार्य अधूरे होने व हल्की गुणवत्ता होने पर सब इंजीनियर सोलंकी व सहायक यंत्री आरएस त्यागी का एक सप्ताह का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

बैठक में नहीं पहुंचे सचिव : सीइओ ने पहाड़गढ़ जनपद की सभी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई। बैठक में चचेड़ी, पचौखरा, खिटोरा, सिंगरौली व चिन्नौनी चंबल पंचायत के सचिव नहीं आए थे। बैठक में न आने पर सीईओ ने इन पांच सचिवों का एक-एक सप्ताह का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। जनपद में कई निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे थे। वे महीनों से बंद पाए गए। बैठक में पहाड़गढ़ जनपद सीईओ एपी प्रजापति, पीसीओ मनरेगा तिलक सिंह सहित अन्य पंचायत के सब इंजीनियर, सहायक यंत्री व पंचायत सचिव मौजूद थे।

राजस्व अधिकारी आरआई, पटवारियों को इतना फ्री हैंड न छोड़ें कि उन पर कोई लगाम न हो

» मुरैना कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में दिए कड़े निर्देश

» जौरा एसडीएम और कैलारस तहसीलदार को थमाया नोटिस

संवाददाता, मुरैना

सरकार की मंशा है कि विवादित-अविवादित आवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र ही उन्हें ऑनलाइन दर्ज कराएं। एक भी आवेदन अलमारियों में शोपीस बनकर नहीं मिले। राजस्व अधिकारी न्यायालय प्रकरणों के निराकरण में अधिक समय दें और एक सप्ताह में एक दिन की बजाए दो या तीन दिन न्यायालय कोर्ट में सुनवाई करें।

यह बात मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने हाल ही में नए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में चल रही राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार, एलके पांडे, समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद थे। वहीं जौरा में एक तिहाई प्राप्त आवेदनों में से मात्र 5 फीसदी आवेदनों का निराकरण होने पर कलेक्टर ने जौरा एसडीएम सुरेश बरहादिया और कैलारस तहसीलदार भरत यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अब कोविड का बहाना न बनाएं

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 834 बंटवारा के आवेदनों में से मात्र 116 प्रकरणों का निराकरण किया गया है यह स्थिति ठीक नहीं है। राजस्व अधिकारी अब कोविड का बहाना न बनाएं। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना अपनी प्राथमिकता समझें और उनका निराकरण कराएं। सीमांकन के प्रकरण में 16 जून से 1 जुलाई तक 407 प्रकरणों में से मात्र 13 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह स्थिति बेहद चिंतनीय है इसमें संयुक्त कलेक्टर समय समय पर तहसीलों का निरीक्षण करें और जो पेंडेंसी रखी है उसे अपनी उपस्थिति में निराकरण कराएं।

लक्ष्य से भटकी राजस्व वसूली

कलेक्टर ने कहा कि जिले के प्रत्येक हल्का में पटवारी तैनात हैं फिर भी आवेदन लंबित हैं। समस्त एसडीएम अपने अपने क्षेत्र के तहसीलदार, पटवारियों के नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों को 10 प्रतिशत चेक कराएं। हमारे हल्का स्तर पर पटवारी और कोटवार उपलब्ध हैं। हमारा सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। जिले में लॉयन आर्डर की स्थिति न बने, पुलिस से पहले राजस्व अधिकारियों के माध्यम से सूचना हमें मिलनी चाहिए। राजस्व वसूली में 1 अप्रेल 2021 से 30 जून तक ऑनलाइन वसूली 43 लाख 81 हजार 273 और ऑफलाइन वसूली 8 लाख 26 हजार 475 की गई है। जबकि वित्तीय वर्ष में 9 करोड की वसूली का लक्ष्य था।

फोन आया तो गिरेगी गाज

कलेक्टर ने कहा कि पटवारियों की मीटिंग, एसडीएम, तहसीलदार हर सप्ताह करें। जिसकी प्रोसीडिंग मुझे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुझे लोगों के प्रतिदिन कॉल आते हैं कि हमारा नामांतरण नहीं हुआ या हमें पीएम किसान का लाभ नहीं मिला। मुझे आगे से किसी भी व्यक्ति का फोन आता है उस क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। अन्यथा अपने अपने न्यायालय में यह सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आवेदन ऐसा लंबित तो नहीं जिसकी वजह से वह वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।

रियायत की जरूरत नहीं

कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारियों की मीटिंग लेने से पहले मीटिंग का एजेंडा बनाएं, जिस बिंदु पर उन्हें निर्देशित करना है ठीक उसे लक्ष्य मानकर उन्हें मीटिंग में निर्देश दें। उसके बावजूद भी जो पटवारी उस कार्य को नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब समय किसी के साथ रियायत करने का नहीं है। अगर आपने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं तहसीलदार, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।

नामांतरण के 13 हजार प्रकरण लंबित

नामांतरण बंटवारे का कार्य किसी कारणवश प्राथमिकता से नहीं हो पाया जिस कारण जिले में 12 हजार 972 प्रकरण लंबित हैं जिसमें 6 हजार प्रकरण और ऑफलाइन के हैं। इन्हें मिलाकर कुल 19 हजार 927 प्रकरण होते हैं इन्हें अगले 2 माह में शत प्रतिशत निराकरण कराएं। इस प्रकार की वर्किंग रही तो राजस्व अधिकारियों से यह कार्य छिन जाएगा। और एकाध प्रांत नहीं तो इस प्रकार के न्यायालयीन कार्य को छीन लिया है। मूल कार्य राजस्व अधिकारियों का भूमि बंटवारा, नामांतरण, अविवादित नामांतरण का ही है।

ग्वालियर में वृहद स्तर पर होगा पौधरोपण

अंकुर अभियानः हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाने वालों का पंजीयन भी होगा

संवाददाता, ग्वालियर

हरियाली अमावस्या आठ अगस्त को ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में वृहद स्तर पर पौधे रौंपे जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत यह पौधरोपण होगा। संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने इस सिलसिले में विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित किए। साथ ही वायुदूत एप पर पौधरोपण करने वाले लोगों का पंजीयन करने की जवाबदेही भी सौंपी। कर्मचारियों की संख्या से 10 गुना पौधे रोपने का लक्ष्य संभाग आयुक्त ने हर विभाग के लिए निर्धारित किया है। यहां मोतीमहल स्थित मानसभागार में आयोजित हुई बैठक में संभाग आयुक्त सक्सेना ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय आकार के गड्ढे में ही पौधा रौंपा जाए। साथ ही पौधे लगभग 6 फीट की ऊंचाई के होना चाहिए।

विभागवार जिम्मेदारी

नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, कृषि, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन इत्यादि विभागों को पौधरोपण के बड़े लक्ष्य दिए गए हैं। इनके अलावा अन्य विभागों को भी उनके कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से पौधरोपण की जिम्मेदारी दी गई।

रख-रखाव की हो व्यवस्था

संभाग आयुक्त ने कहा कि जन सामान्य को अंकुर अभियान से जोड़ने के लिए उनके मोबाइल फोन में वायुदूत एप डाउनलोड कराकर उनका पंजीयन कराएं। पौधों के फोटोग्राफ निर्धारित अंतराल से अपलोड किए जाएं, जिससे पौधों के प्रति लोगों की आत्मीयता रहे और लगाए गए पौधे पेड़ बन सकें। जो भी पौधा रौंपा जाए उसके लिए पानी और रख-रखाव की पुख्ता व्यवस्था हो, ताकि लगाए सभी पौधे पेड़ का रूप ले सकें।

दतिया कलेक्टर ने बेलपत्र का लगाया पौधा

इधर, अंकुर अभियान के तहत दतिया जिले में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए जा रहे हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने स्वामी जी महाराज कॉलेज में बेलपत्र का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि वृक्षों का पर्यावरण संतुलन में अपना विशेष महत्व है। वृक्षों के महत्व को कोरोना काल में हम सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके है। आज आवश्यकता है कि आज हम संकल्प लेकर कम से कम एक पौधा रोपित कर उसकी परवरिश की भी जिम्मेदारी लें। इस अवसर पर पंचायत के अतिरिक्त सीईओ धनंजय मिश्रा, कॉलेज की ओर से प्रणव ढेंगुला आदि उपस्थित थे।

एमएसपी पर खरीदे गए 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं

» 49.16 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 85,581 करोड़

» ग्यारह राज्यों के किसानों को करोड़ों रुपए की हुई आय

संवाददाता, भोपाल/ नई दिल्ली

देश में इस बार सरकारी दाम पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए अधिकतर राज्यों में पूरा हो चुका है। सरकार के आंकड़े के अनुसार, अब तक (07.07.2021 तक) 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। यह अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है। पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 49.16 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में समर्थन मूल्यों पर हुए खरीदी कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्हें 85,581.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के

6,02,295 किसानों को 5,193.08 करोड़ रुपए की आय हुई है।

लाखों किसानों को लाभ

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस साल 11.82 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई है। अब तक लगभग 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 387.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। मौजूदा सत्र में गेहूं खरीद कार्य से लगभग 49.16 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

इन फसलों की भी खरीद

खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत 07.07.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 9,84,202.49 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है।

नमी के अभाव में सोयाबीन उड़द की बोवनी से बचें किसान

टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही तकनिकी सलाह

संवाददाता, टीकमगढ़

सोयाबीन और उड़द की बोवनी जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक उचित होती है, लेकिन इस बार मानसून देरी से आ रहा है, इसलिए नमी के अभाव में बोवनी करने से बचना चाहिए, क्योंकि चार इंच बारिश होने पर ही बोवनी करना चाहिए। यह सलाह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़ द्वारा दी जा रही है।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे एक फसल की एक किस्म न बोकर दो या तीन किस्मों की बोवनी करें। इससे फसलों का जैविक/अजैविक दबाब से बचाव होता है। जोखिम से बचने के लिए मुख्य फसल के साथ अंतवती फसलों के रूप में सोयाबीन की चार कतारों के बाद दो कतार अरहर की लगाने से अतिरिक्त आय किसान प्राप्त कर सकते हैं। खेत की अंतिम जुताई/बखरनी से पहले अनुशंसित गोबर की सड़ी खाद (14 टन/एकड़) की दर से खेत में मिलाकर कल्टीवेटर व पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। जब बोवनी संभव हो तो चौड़ी क्यारी पद्धति/कूड़ मेड़ नाली पद्धति से ही बोवनी करें जिससे सूखे/अतिवर्षा के दौरान उत्पादन प्रभावित न हो। इन मशीनों के अभाव में किसान अन्य उपलब्ध सीड्ड्रिल में पंजा लगाकर से भी बोवनी कर सकते हैं।

सीड-कम-फर्टी ड्रील का प्रयोग करें

बोवनी के बाद 3/6/9 कतारों के बाद नालियां बनाने की व्यवस्था करें जिससे अतिरिक्त पानी का निकास और सूखे की स्थिति में जल संचय की व्यवस्था हो सके। कतारों की दूरी और बीज दर सोयाबीन की बोवनी के लिए 45 सेमी कतार से कतार की दूरी पर और न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकुरण के आधार पर बीजदर (55 से 75 किग्रा/हे.) का उपयोग करें। खाद व उर्वरकों का उपयोग सोयाबीन के लिए अनुशंसित पोषक तत्व की पूर्ति के लिए उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में बोवनी के समय करें। इसके लिए सीड-कम-फर्टी ड्रील का प्रयोग किया जा सकता है।

बीज बोने से पहले उपचारित कर लें

बीज उपचार के लिए पेनफ्लूफेन प्लस ट्राय क्लोक्सीस्ट्रोबीन अथवा बीटावेंक्स अल्ट्रा 2.5 ग्राम/किग्रा बीज अथवा जैविक फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडरमा 10 ग्राम/ मिली/किग्रा बीज बोने से पहले उपचारित कर लें। राइजोबियम व पीएसबी दोनों 5 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। पीला मोजक जिन क्षेत्रों में पहले हुआ है। साथ ही थायोमिथाक्साम 30 एफएस (10 मिली/किग्रा बीज) या इमिडाक्लोरोप्रिड 48 एफएस (1.2 मिली/किग्रा बीज) से उपचार करना चाहिए। सफेद सूंडी के नियंत्रण के लिए बोवनी से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड का उपचार नियंत्रण में सहायक है। खरपरतवार नियंत्रण के लिए डोरा/ कुल्फा/ हाथ से निदाई कर सकते हैं।

ऐसे करें रासायनिक का उपयोग

रासायनिक खरपरतवार नियंत्रण के लिए सभी फसलों के लिए बोवनी के बाद अंकुरण के पहले पेंडीमिथलीन 30 ईसी शाकनासी की मात्रा 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ फ्लेट फेन या फ्लेट जेट नोजल से छिड़काव करें। सोयाबीन की खड़ी फसल में बोवनी के 15-20 दिन बाद इमेजाथाइपर 10 एसएल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा का उपयोग करें।

नई किस्मों का करें चयन

सोयाबीन के लिए जेएस 20-29 (अवधि 95-100 दिन), जेएस 20-34 (अवधि 86-88 दिन), जेएस 20-69 (अवधि 91-97 दिन) जेएस 20-116 (अवधि 95-100 दिन), पीएस 20-98 (अवधि 96-101 दिन), एनआरसी 127 (अवधि 100-104 दिन) उड़द /मुकुदरा, इंद्रा उड़द-1, प्रताप उड़द-1, कोटा-3 कोटा-4 आदि नई किस्मों का चयन करना चाहिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले-

खत्म नहीं होंगी मंडियां

अब 25 योजनाओं तक के लिए ब्याज में छूट का प्रावधान

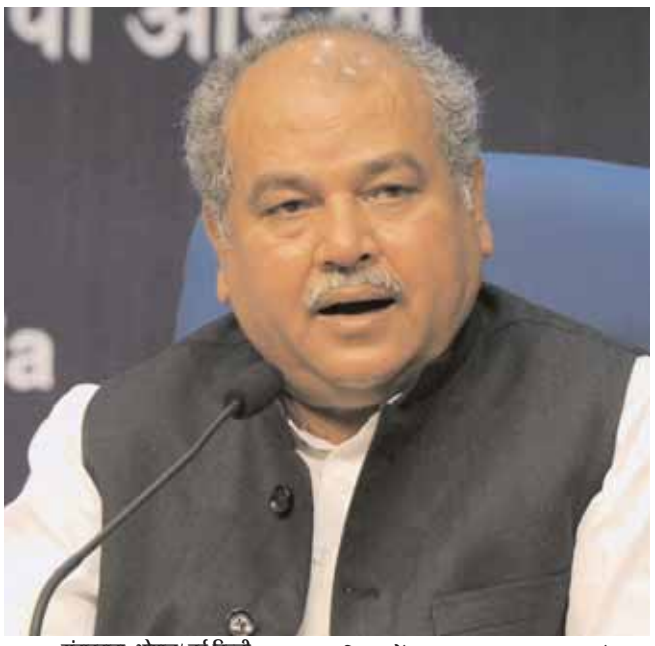

संवाददाता, भोपाल/ नई दिल्ली

आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि अवंसरचना के लिए जारी किए गए एक लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल अब मंडियां भी कर सकेंगी। मंडियों समाप्त नहीं होंगी। हमारी सरकार उन्हें और मजबूती देने के लिए काम कर रही है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणा होती है हम उसे पूरा करते हैं। बजट में हमने कहा था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और उन्हें मजबूत किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना क्षेत्र के लिए जारी एक लाख करोड़ रुपए के फंड का उपयोग मंडियों के विकास में किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग कर सकेंगी। इसी के साथ राज्य सरकार के स्वयंसहायता समूह और कोऑपरेडिट भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि अभी तक ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ, एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह अगर एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट होगी। पहले इसमें एक ही परियोजना मान्य थी। अब यदि व्यक्ति एक से अधिक या 25 तक परियोजना शुरू करता है तो उसे हर परियोजना के लिए ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार की गारंटी की प्रात्रता रहेगी। राज्य सरकार के संस्थाओं पर 25 से अधिक परियोजनाओं पर छूट रहेगी।

बढ़ी पैदावार और खरीद

तोमर ने कहा कि भारत सरकार का कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक कदम है। मैं समझता हूं समय रहते किसान यूनियन को इसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश महत्व को समझ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एपीएमसी समाप्त नहीं होगी। एपीएमसी और सशक्त हो, किसानों के लिए उपयोगी हो यह मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इसी लिए एक लाख के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसे पात्र इकाई माना गया है। इससे एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पैदावार बढ़ रही है और खरीद भी बढ़ रही है।

» बिना प्रचार प्रसार के हर वर्ष सैंकड़ों पौधे लगाए जा रहे

» 109 वर्ष प्राचीन बगिया में पंचवटी वृक्षों की कमी नहीं

होशंगाबाद में स्वदेशी पेड़ों का गुरुकुल

पंकज शुक्ला, होशंगाबाद

प्रदेश व देश के प्राचीन गुरुकुल परिवार ने पांच हजार पौधों को बनाया है पेड़। बिना किसी प्रचार प्रसार के हर वर्ष सैंकड़ों पौधे लगाए जाते हैं। उनका उचित संरक्षण भी किया जाता है। नर्मदा तट की हरी भरी वादियों में समाहित 109 वर्ष प्राचीन गुरुकुल की बगिया में पंचवटी वृक्षों की भी कमी नहीं हैं। जिनमें वट, पीपल, आंवला, नीम, अशोक के अलावा और भी दर्जनों प्रजाति के स्वदेशी पेड़ हरियाली से गुरुकुल को सराबोर कर रहे हैं। औषधीय के साथ ही फलदार, छायादार पौधों के साथ ही सब्जी और खाद्यान्न की पैदावार होती है। हर वर्ष बारिश के मौसम में पौधे लगाने का क्रम चलता रहता है। गुरुकुल परिवार का पौधों से विशेष लगाव रहता है। यहां पर पौधे व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं। इन पौधों का संरक्षण पूरा गुरुकुल परिवार करता है।

फलदार पेड़ों की भरमार

गुरुकुल में फलदार,छायादार पेड़ों की भरमार है। यज्ञशाला के पास आम की सात बेरायटी, व्यायाम शाला की ओर आंवले की तीन बेरायटी। इसी तरह भोजनशाला की तरफ अनेक किस्म के अमरुद, केले, अनार, चीकू, नींबू, सीताफल, जामुन, बादाम, नारियल आदि अनेक फलदार पेड़ लगे हुए हैं। जिनमें हर वर्ष फल आते हैं।

जन्मदिन पर रोपते हैं पौधे

गुरुकुल के पेड़ किसी सरकारी कार्यक्रम या कोई विशेष पौधारोपण अभियान का हिस्सा नहीं है। यह तो गुरुकुल के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, आचार्य या ब्रम्हचारियों के जन्मदिन हो या गुरुकुल स्थापना दिवस हो या फिर इसी तरह के कोई कार्यक्रम होने पर लगातार पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों का संरक्षण गुरुकुल के अध्यक्ष स्वामी ऋतस्पति परिव्राजक व प्रधानाचार्य स्वामी सत्यसिंधु आर्य के मार्गदर्शन में किया जाता है।

हर तरह के फूलदार पौधे

गुरुकुल में हर तरह के फूलदार पौधे की बगिया आकर्षित करती है। इसके अलावा आकर्षक पौधे भी बड़ी मात्रा में लगे हैं। मुख्य द्वार से लेकर पूरे परिसर की बाउंड्री में अलग-अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। जिन्हें व्यवस्थित रूप भी दिया जाता है। जैसे यज्ञशाला के पास के विशाल पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे शीतल छाया में गोलाकार चबूतरा बना दिया है। जहां सैंकड़ों लोग बैठ सकते हैं।

हर तरह की फसल

गुरुकुल की भूमि में धान, मक्का, अरहर, तिल, जो, गेहूं, चना, मूंग, उड़द सहित अन्य सभी तरह की फसल लगाई जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में सब्जी भी लगाई जाती है। जिससे भी पूरा वातावरण हरा भरा रहता है।

इनका कहना है

जब कोई पेड़ सूख जाता है या हवा में गिर जाता है तो उस स्थान पर तुरंत दूसरा पेड़ लगा देते हैं, जिससे कि पेड़ की कमी नहीं हो। यहां पर औषधीय पौधे भी काफी संख्या में लगे हैं। पूरा गुरुकुल हरी भरी चादर से आच्छादित है। गुरुकुल की भूमि पर जिस तरफ भी नजर दौड़ती है उस तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। पेड़ों से पूरा वातावरण व गुरुकुल का पर्यावरण सुंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

सत्यसिंधु आर्य, प्रधानाचार्य, गुरुकुल, होशंगाबाद

भिंड में पेड़ वाले दुबे जी...!

» नौकरी के दौरान कटवाए पेड़, सेवानिवृत्ति होने के बाद पौधारोपण का दिखा जुनून

» बांध निर्माण के दौरान सब इंजीनियर को पेड़ कटवाने ने कर दिया था बेचैन

नीरज शर्मा, भिंड

देशभर में बीहड़ और डकैतों के चर्चित भिंड-चंबल अंचल की अब तस्वीर बदलने लगी है। अब यहां लोग बतों-बातों में बंदूक नहीं चलाते, बल्कि हरियाली और पौधरोपण के लिए मिशाल बन रहे हैं। दरअसल, नौकरी के दौरान दी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए पेड़ काटने के दुख ने एक सब इंजीनियर का जीवन ही बदल दिया। सेवानिवृत्ति के बाद अब वे पेड़-पौधों को लगाने और उन्हें बचाने के जुनून के हमसफर बन गए हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रहने वाले 69 वर्षीय सुरेश चंद्र दुबे की। वे अब तक करीब 11 हजार पौधे लगा चुके हैं, इनमें से 10 हजार तो पेड़ बन चुके हैं। वे पौधे लगाने के बाद उनकी देखरेख की चिंता भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय समितियां तैयार की हैं। अपने खर्चे से उन्होंने ट्री गार्ड भी लगवाए हैं। भिंड जिले के लहार तहसील मुख्यालय में वार्ड 14 की महुआ कॉलोनी में रहने वाले सुरेश चंद्र दुबे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके जुनून को देखते हुए यहां लोग उन्हें पेड़ वाले दुबे जी कहने लगे हैं।

पौधों को संभालने का संकल्प: उप्र के सिंचाई विभाग में सब इंजीनियर की नौकरी में रहते ललितपुर में बांध बनाने के लिए उन्हें पेड़ काटने पड़े थे। इस घटना ने उनके मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ा। वे बेचैन रहने लगे। 2013 में रिटायर हुए तो अधिक से अधिक पौधे रोपने और उन्हें संभालने का संकल्प लिया। संकल्प की शुरुआत भी ललितपुर से ही की। न केवल बांध के आसपास 600 पौधे लगाए, बल्कि सेवानिवृत्त हो जाने के एक साल तक ललितपुर में ही रहकर पौधों की पेड़ बनने तक देखरेख की।

दस हजार पौधे बन गए पेड़: फिर सुरेश चंद्र दुबे पैतृक गांव उप्र के जिला जालौन में आने वाले खकशीश चले गए। वहां भी पौधे लगाने का काम शुरू किया। देखरेख करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा। सबकी मदद से करीब वहां दो हजार पौधे लगाए। जालौन में डेढ़ साल तक रहने के बाद 2015 में लहार आने पर यह क्रम जारी रखा। यहां अब तक 8400 पौधे लगा चुके हैं। उनके द्वारा लगाए गए 11 हजार पौधों में से 10 हजार पेड़ बन चुके हैं।

इनका कहना है

पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुरेश चंद्र दुबे अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे सीख लेकर अन्य लोगों को भी इस तरह के प्रयास शुरू करने चाहिए।

-आरए प्रजापति, एसडीएम, लहार

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)